भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2289**
जिसका उत्तर 19 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है ।
28 अग्रहायण, 1947 (शक)

## सरकारी ईमेल अकाउंट को ज़ोहो में स्थानांतरण (माइग्रेशन)

**2289. श्री के. आर. एन. राजेश कुमार:**

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने केंद्रीय सरकारी ईमेल अकाउंट और प्रोडक्टिविटी सुइट लाइसेंस, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से ज़ोहो कॉर्पोरेशन प्लेटफ़ॉर्म में स्थानांतरित (माइग्रेट) किए गए;
(ख) इस परियोजना के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी वित्तीय मंजूरी दी गई है और अनुबंध की तिथि और अवधि क्या है; और
(ग) इन अकाउंट के ज़ोहो में स्थानांतरण (माइग्रेशन) से पूर्व लेखा परीक्षाएँ करने वाली संस्थाओं, लेखा परीक्षाओं की तिथियों और उनके निष्कर्षों सहित की गई सुरक्षा लेखा परीक्षाओं का ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)**

**(क)** से **(ग):** सरकार अपने मंत्रालयों और विभागों के लिए एक मजबूत, संप्रभु और सुरक्षित आधिकारिक ई-मेल प्रणाली के महत्व को पहचानती है।
तदनुसार, सरकार का आदेश है कि आधिकारिक संचार के लिए केवल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-मेल सेवाओं का उपयोग किया जाएगा।
इसे सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने एनआईसी के माध्यम से मार्च 2024 के महीने में एक मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) – मैसर्स ज़ोहो का चयन किया है, जो सभी सरकारी उपयोगकर्ताओं का समर्थन करने में सक्षम एक मजबूत क्लाउड-आधारित ईमेल समाधान के लिए है।
जोहो प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट किए गए खातों की संख्या लगभग 12.68 लाख है।
भुगतान ज़ोहो प्लेटफ़ॉर्म पर माइग्रेट किए गए ईमेल खातों की वास्तविक संख्या के आधार पर किया जाता है। ईमेल खातों के लिए मासिक मूल्य क्रमशः 30 जीबी और 100 जीबी मेलबॉक्स आकार के लिए 200 रुपये और 300 रुपये है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, कुल व्यय 41.33 करोड़ रुपए था और चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, अब तक किया गया व्यय 120 करोड़ रुपए है।
सेवा प्रदाता का चयन एक खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं और सरकारी उपयोगकर्ताओं के नामित समूहों के साथ अवधारणा का प्रमाण (पीओसी) शामिल था। यह परियोजना "मेक इन इंडिया" अनुपालन पर जोर देती है और यह सुनिश्चित करती है कि सरकार अनुबंध के तहत उत्पन्न सभी डेटा और बौद्धिक संपदा का पूर्ण स्वामित्व बनाए रखे।
नए जोहो प्लेटफॉर्म पर ईमेल सेवा के लाइव होने के बाद, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के उपयोगकर्ताओं से ऑनलाइन प्रतिक्रिया एकत्र की गई। सेवा प्रदाता - मैसर्स जोहो एक पंजीकृत भारतीय इकाई है जो भारतीय कानूनों और अधिकार क्षेत्र के अधीन है।
सेवा प्रदाता के साथ अनुबंध डेटा संप्रभुता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करता है। सुरक्षित प्रवासन और परिनियोजन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सुरक्षा मूल्यांकन किए गए हैं:

- मई 2024 में मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी), एमईआईटीवाई द्वारा व्यापक सुरक्षा ऑडिट
- सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक), एमईआईटीवाई द्वारा अगस्त 2025 में दूसरा पूर्ण सुरक्षा ऑडिट

प्राथमिक और आपदा रिकवरी डेटा केंद्रों सहित क्लाउड-आधारित समाधान भौतिक रूप से भारत के भीतर स्थित हैं और किसी भी डेटा को देश के बाहर साझा या दोहराया नहीं जा सकता है।

******